

समाधान दिवस में फरियादियों की जुटी भीड़

(आधुनिक समाचार सेवा)

सरकार अहमद

फूलपुर। थाना फूलपुर परिसर में समाधान दिवस की अध्यक्षता सीओ रामसाहा ने करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जन समस्याओं के प्रति गंभीर है। लिहाजा पुलिसकर्मी दरबारीस्तर से करते हैं। जानीवी विवाद हुई क्वाड्री की जड़ बन रहे हैं। आज के दिवस पर लोग खाकी के पास कुछ उम्मीद लेकर आते हैं। इधर कई वर्षों के बाद आज बंपर भीड़ दिखी। खास बात यह रही की सरकार ने महिलाओं की बात सुनने को तरजीह की है। अतः अब महिलाएं कसरत से आने

लगी है। कुल 18 दरखास्ते आई। जिनमें इन्द्राज करके संबंधितों को दे रखा गया। तीन पुलिस परिवारों से संबंधित तुरंत निस्तारित कर दिए गए। कई जगह तो ऐसे एच औ अमित कुमार राय ने कठाल पुलिस टीम रवाना कर दी। सीओ राम सागर तथा थानाध्यक्ष ने 2 बजे से ज्यादा एक घण्टा तक दिवस में कठाल के आने की सुचना के चलते भीड़ बढ़ गई थी। मौके पर छाकी इंजार विभाग कुमार मिश्र, माजिद खान, सुनील प्रसाद, जय सिंह यादव, गोतम, राजेश वर्मा आदि के अलावा अधिकारी लेखपाल व कानूनगों मौजूद रहे।



जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद, जनपद- सीतापुर में सड़क सुरक्षा संबंधी जागरूकता अभियान कार्यक्रम का किया गया संचालन

(आधुनिक समाचार सेवा)

आशीष त्रिवेदी

सीतापुर। इस अभियान अंतर्गत आज संस्थान में सड़क सुरक्षा एवं यातायात से संबंधित एक कार्यशाला

अंतर्गत सर्वप्रथम एआरटीओ मोदीदया एवं वरिष्ठ प्रवक्ता के द्वारा दीप प्रज्ञल कर कार्यक्रम का शुभाभियान किया गया तथा प्रशिक्षकों द्वारा सरसरी बेंदा एवं स्पार्ट

सरकार अहमद

फूलपुर। बीती शाम तेज रफ्तार से आई बड़वाहीय आंखी नुमा तूफान ने जहां तमाम पेंडों के नुकसान पहुंचाया। वहीं विद्युत व्यवस्था थड़ाम हो गई। खसार उप केंद्र की थर्नी श्री का पोल 220 महावीरन के पास गिरा तो उसको बनने में



बेढ़नगे ब्रेकर पर दो ट्रके भिड़ी, एक घायल

(आधुनिक समाचार सेवा)

सरकार अहमद

फूलपुर। फूलपुर मुकारकपूर रोड के नोडल अधिकारी संस्थान के प्रवक्ता श्री ईश महान शुक्र के द्वारा कार्यशाला के उद्देश्यों से अवगत कराया गया। तत्पश्चात संस्थान के ही वरिष्ठ प्रवक्ता श्री शुभम शूक्र जी के द्वारा प्रशिक्षकों को संबोधित करते हुए यातायात को महत्व समझाया गया। कार्यक्रम में आगे सड़क सुरक्षा पर प्रशिक्षकों द्वारा एक लघु नाटक प्रस्तुत की गई। एआरटीओ महादया द्वारा प्रशिक्षकों को सड़क सुरक्षा विषय पर जागरूक करते हुए उनसे जनदर्शकों एवं छात्र छात्राओं को भी जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती माला बाजेई प्रशासन उपस्थित रही। इस कार्यशाला के



आज किसान गोष्ठी का आयोजन.....

(आधुनिक समाचार सेवा)

सरकार अहमद

फूलपुर। पानी की टंकी पर आयोजित किया गया था देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लाइव लिंगी श्री उसको नियमित रूप से किसानों की धान की नरसीरा एवं खेजी की चैन कम्पनी इंजारी जीवंत खेजी एवं हरी खेज की जानकारी जीवंत खेजी के साथ



प्रयागराज। कांग्रेस नेता इश्वरदास उड़ा ने कई बार नगर निगम से इस खंभे की हाफ्टोने के लिए के कहा इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं कुंभकरण की नीद से हुए हैं हुए हैं नगर निगम के अधिकारी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं नगर निगम बहादुरगंज जीटी रोड शिवाजी पार्क लंग मंडी के एक बांका करता रहे हैं।

आभियुक्त तमंचा व कारतूस सहित गिरफ्तार

(आधुनिक समाचार सेवा)

सरकार अहमद

फूलपुर। थानाध्यक्ष फूलपुर अमित कुमार राय के नेतृत्व में उन्नीसका

बांका करता रहे थे एक अदद तमंचा 315 बांका व एक अदद नियंता कारतूस 315 बांका के साथ गिरफ्तार करने गारी टीम में उप निरीक्षक विभाग कुमार मिश्र, उपनिरीक्षक सुभाष गौतम, कांस्ट्रक्ट्रीजी सिंह, का० सौरभ सिंह आदि रहे।

विनय कुमार मिश्र मयपुलिस टीम द्वारा दिनांक 29 मई 2022 को

अधिवक्ता संघर्ष समिति ने जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों की गैर हाजिरी पर व्यक्ति की चिंता.....

(आधुनिक समाचार सेवा)

सरकार अहमद

फूलपुर। अधिवक्ता संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्रीम अमित डुवोकेट ने कैप्स में एक बैठक कर तहसील की खिली उड़ाई जा रही है। इसके चलते अधिकारियों की अधिक फौजी हो रही है। जो काफी दूर से चलकर आते हैं।

जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सम्पूर्ण समाधान दिवस पर झूंसी, सरायड़नायत एवं उत्तरांव थाने में सुनी जनता की समस्यायें प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु तत्काल राजस्व एवं पुलिस टीम का गठन कर मौके पर किया रवाना

(आधुनिक समाचार सेवा)

विश्वाल गुप्ता

थाना फूलपुर। जिलाधिकारी श्री संजय कुमार खत्री एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अजय कुमार ने सम्पूर्ण समाधान दिवस पर थाना झूंसी, सरायड़नायत एवं उत्तरांव पहुंचकर जनता की समस्याओं को सुना तथा संबंधित राजस्व विभाग एवं पुलिस टीम की विशेषता किया जाये। जनता की खिलायतों में लापरवाही या उदासीनता कर्तव्य क्षम्य नहीं होगी। जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सर्वथान्त्रिक विभाग के संयुक्त टीम को मौके पर निस्तारण के लिए भेजा। उन्होंने राजस्व विभाग तथा पुलिस टीम के निर्देशित किया कि जो भी आवेदन आ रहे हैं, उसका 3 दिनों में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाये। जनता की शिकायतों में लापरवाही या उदासीनता कर्तव्य क्षम्य नहीं होगी। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने सर्वथान्त्रिक विभाग के संयुक्त टीम को भेजा। उन्होंने राजस्व विभाग एवं पुलिस टीम के निर्देशित किया कि जो भी आवेदन आ रहे हैं, उसका 3 दिनों में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाये। जनता की शिकायतों में लापरवाही या उदासीनता कर्तव्य क्षम्य नहीं होगी। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने सर्वथान्त्रिक विभाग के संयुक्त टीम को भेजा। उन्होंने राजस्व विभाग तथा पुलिस टीम के निर्देशित किया कि जो भी आवेदन आ रहे हैं, उसका 3 दिनों में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाये। जनता की शिकायतों में लापरवाही या उदासीनता कर्तव्य क्षम्य नहीं होगी। जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सर्वथान्त्रिक विभाग के संयुक्त टीम को भेजा। उन्होंने राजस्व विभाग एवं पुलिस टीम के निर्देशित किया कि जो भी आवेदन आ रहे हैं, उसका 3 दिनों में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाये। जनता की शिकायतों में लापरवाही या उदासीनता कर्तव्य क्षम्य नहीं होगी। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने सर्वथान्त्रिक विभाग के संयुक्त टीम को भेजा। उन्होंने राजस्व विभाग एवं पुलिस टीम के निर्देशित किया कि जो भी आवेदन आ रहे हैं, उसका 3 दिनों में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाये। जनता की शिकायतों में लापरवाही या उदासीनता कर्तव्य क्षम्य नहीं होगी। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने सर्वथान्त्रिक विभाग के संयुक्त टीम को भेजा। उन्होंने राजस्व विभाग एवं पुलिस टीम के निर्देशित किया कि जो भी आवेदन आ रहे हैं, उसका 3 दिनों में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाये। जनता की शिकायतों में लापरवाही या उदासीनता कर्तव्य क्षम्य नहीं होगी। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने सर्वथान्त्रिक विभाग के संयुक्त टीम को भेजा। उन्होंने राजस्व विभाग एवं पुलिस टीम के निर्देशित किया कि जो भी आवेदन आ रहे हैं, उसका 3 दिनों में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाये। जनता की शिकायतों में लापरवाही या उदासीनता कर्तव्य क्षम्य नहीं होगी। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने सर्वथान्त्रिक विभाग के संयुक्त टीम को भेजा। उन्होंने राजस्व विभाग एवं पुलिस टीम के निर्देशित किया कि जो भी आवेदन आ रहे हैं, उसका 3 दिनों में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाये। जनता की शिकायतों में लापरवाही या उदासीनता कर्तव्य क्षम्य नहीं होगी। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने सर्वथान्त्रिक विभाग के संयुक्त टीम को भेजा। उन्होंने राजस्व विभाग एवं पुलिस टीम के निर्देशित किया कि जो भी आवेदन आ रहे हैं, उसका 3 दिनों में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाये। जनता की शिकायतों में लापरवाही या उदासीनता कर्तव्य क्षम्य नहीं होगी। जिल

सम्पादकीय

नेशिचत वैश्विक परिवहन कारण यह आवश्यक सा है कि संघर्ष

अनिश्चित वैशिक परिदृश्य के कारण यह आवश्यक हो गया है कि महंगाई पर

लगाम लगाई जाए

लगातार परेशान करती महंगाई के बीच शनिवार की शाम एक राहत भरी खबर आई। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाने का लान किया, जिससे बेलगाम महंगाई पर कुछ लगाम लगने की उमीद बढ़ी है। इससे जहां लोगों का आवाजाही से जुड़ा खर्च घटेगा, वहीं आवश्यक वस्तुओं की दुलाई सस्ती होने से भी राहत मिलेगी। पिछले कुछ अर्से से प्रत्येक वर्ष पर महंगाई का असर दिखने लगा था। विशेषकर निम्न-आय वर्ग के लिए यह नासूर बनती जा रही थी। इस तबके की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा खानपान और ईंधन पर खर्च होता है। इस कारण बढ़ती कीमतों से उसका बजट बिगड़ता जा रहा था। ऐसे में सरकार के लिए कोई राहत देना आवश्यक हो गया था। इससे पहले गत नवंबर में भी केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाया था, लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद कच्चे तेल की कीमतों में बढ़तीरी से उस कटौती का असर जाता रहा। महंगाई इस समय केवल भारत की समस्या नहीं है। तमाम देश इससे बुरी तरह प्रत्यक्ष है। भारत में तो करोब छह प्रतिशत मुद्रास्फीति का लक्ष्य भी सहज मान लिया जाता है। वहीं अमेरिका इसके लिए अधिकतम दो प्रतिशत का लक्ष्य तय करता है, लेकिन वहां मुद्रास्फीति की दर 8.3 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई है, जो महंगाई की विकराल स्थिति को दर्शाता है। यूरोप का भी यहीं हाल है। कुल मिलाकर अधिकांश देश अभी महंगाई की मार से बेहाल हैं। फिलहाल रूस-यूक्रेन युद्ध इसका तात्कालिक कारण है। इस युद्ध ने दुनिया भर में तेल और गैस के दाम आसमान पर चढ़ा दिए हैं। खाद्य वस्तुओं के दाम भी उसकी चपेट में आ गए हैं। रूस और यूक्रेन दुनिया को गेहूं की बड़ी पैमाने पर आपूर्ति करते हैं। यूक्रेन सूखजमुखी तेल का भी बड़ा उत्पादक है। उसके रणक्षेत्र में बदलने से इन उत्पादों की आपूर्ति पर असर पड़ा है। इस लड़ाई ने वैश्विक आपूर्ति शुंखला को भी छिन्न-भिन्न कर दिया है। केवल यहीं नहीं, बल्कि इसके कारण आपूर्ति केंद्रों के समीकरण भी गड़बड़ा गए हैं और उन्हें नए सिरे से तय करना पड़ रहा है। यह प्रक्रिया खर्चीली होने के साथ ही ज्यादा समय भी ले रही है। इससे वस्तुओं के दाम बढ़े? के साथ ही उनकी आपूर्ति का समय प्रभावित हो रहा है, जिससे उनकी किलूत पैदा हो रही है। इस कारण भी कीमतों में बढ़तीरी का रुझान दिख रहा है। वहीं चीन में कोविड के विस्फोट एवं उस पर काबू पाने की कड़ी नीति ने आर्थिक मोर्च पर एक नया जोखिम उत्पन्न कर दिया है। भारत बड़ी पैमाने पर कच्चे तेल, गैस के अलावा तमाम औद्योगिक जिंसों और खाद्य तेल जैसी वस्तुओं का आयात करता है तो उस पर इनका असर पड़ा? स्वाभाविक है। इसे आयातित महंगाई का नाम दिया जाता है। इसका आशय है आयात की जाने वाली वस्तुओं के कारण बढ़े? वाली महंगाई। सामान्य परिस्थितियों में भारतीय महंगाई परिदृश्य में आयातित महंगाई का अनुपात करीब 28 से 30 प्रतिशत के दायरे में होता है, लेकिन इस समय यह 60 प्रतिशत से भी ऊपर है। यह स्थिति की गंभीरता को दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि वैश्विक रुझान किस प्रकार भारत में महंगाई की आग को हवा दे रहे हैं। कीमतों पर असर डालने के अलावा ये आर्थिक गतिविधियों की धारा कुंद करने पर भी आमदाद है। जैसे चीन में कोविड के कारण लगे लाकडाउन से देसी कंप्यूटर हार्डवेयर, कंज्यूमर ड्यूरोबल्स और दूरसंचार क्षेत्र की आपूर्ति पर असर पड़ा है। भारत अपनी आवश्यकता का करीब 53 प्रतिशत कंप्यूटर हार्डवेयर, 52 प्रतिशत कंज्यूमर ड्यूरोबल्स और 43 प्रतिशत दूरसंचार उपकरण एवं उनके निर्माण में आवश्यक कल्पुर्ज चीन से आयात करता है। ऐसे में यदि यह गतिरोध लंबा चला तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इस आयातित महंगाई का दीर्घकालिक समाधान यहीं है कि जहां भारत हाइक्रोबार्बन पर अपनी निर्भरता घटाए, वहीं अधिक से अधिक वस्तुओं का घेरेलू उत्पादन करे। सरकार द्वारा हारित ऊर्जा पर जोर और सेमीकंडक्टर जैसे उदयोग की स्थापना के लिए प्रोत्साहन इस दिशा में स्वागतयोग्य है, लेकिन उनके अपेक्षित परिणाम आने में समय लगेगा। मौजूदा परिस्थितियों की बात करें तो पेट्रोल-डीजल पर कर की दर घटाने की बहुत ज्यादा गुंजाइश न होने के बावजूद सरकार को ऐसा करने के लिए विवश होना पड़ा।



मुस्लिमों के हित में है समान नागरिक संहिता, जानें एक्सपर्ट के विचार

देश में अन्य अनेक मुद्दों पर चर्चा के बीच समान नागरिक संहिता पर भी बहस जारी है। जहां कुछ राज्य सरकारें इसका समर्थन कर रही हैं, वही मुस्लिम पर्सनल लार्ड जैसे संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। उत्तराखण्ड सरकार ने तो इसके लिए एक आयोग तक का गठन कर दिया है। कुछ और राज्य सरकारें इसी दिशा में पहल कर रही हैं। एक मुस्लिम महिला होने के नाते मेरा मानना है कि मुस्लिम समुदाय को समान नागरिक संहिता का समर्थन करने में सबसे आगे होना चाहिए। इस संहिता का उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था बनाना है, जहां हर भारतीय नागरिक कानून के समक्ष समान हो। भारत में जहां आपराधिक कानून देश के हर नागरिक पर समान रूप से लागू होते हैं, वही सिविल मामलों में कई समुदायों के अपने पर्सनल यारी निजी कानून हैं, जो कहीं-कहीं तो संहिताबद्ध भी नहीं हैं। गोवा में किसी तरह के निजी कानून लागू नहीं हैं। वहां समान नागरिक संहिता लागू है और उससे किसी को परेशानी नहीं। समान नागरिक संहिता के तहत गिराव, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार, गुजारा भत्ता, संपत्ति आदि से जुड़े मामले आते हैं। साफ है कि समान संहिता महिलाओं को जुड़ी समस्याओं और मुद्दों पर सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव डालने वाली है। हालांकि सभी समुदायों के निजी कानूनों में समय के साथ थोड़ा-बहुत बदलाव करके उन्हें महिलाओं के हित में करने की कोशिश की गई है और इसमें कुछ सफलताएं भी मिली हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। दरअसल निजी कानून मूलतः पूराने रस्मों-रिवाज, मान्यताओं और पृथक्सत्तात्मक धार्मिक व्याख्याओं पर ही आधारित है। इक्ष्यहू कोड बिल के तहत अब इक्ष्यहू महिलाएं परिवार की संपत्ति में बराबर की हकदार हैं, परंतु निजी कानूनों में लैंगिक असमानता के चलते मुस्लिम

महिलाओं को इस मामले में सीमित अधिकार ही हासिल है। मुस्लिमों में वैष्णव अपापाना की कठुना आपि

अधिकार मुस्लिम पुरुषों को प्राप्त है। जहां 'खुला' के जरिये तलाक के बादी अस्ति अविवाहित होते हैं

छ राज्यों में यह कानून बदला
या है। मुस्लिम महिला (तलाक पर
अधिकार में का गंभीरा) अधिकारा

म नहीं हुई है। बाल विवाह भी जी कानून का हिस्सा रहा है, केन ए बाल विवाह निषेध (शोषण) अधिनियम के बाद मुस्तिम पुदय को भी नए नियम का पालन करना होगा। समाज में महिलाओं स्थिति को देखते हुए डा. भीमराव बेडकर ने कहा था कि वे किसी समाज की प्रगति को वहाँ की महिलाओं की स्थिति से मापते हैं। देव हम किसी भी समाज का ध्यान चाहते हैं तो हमें उस समाज महिलाओं के सशक्तीकरण की रसा में कार्य करना होगा। इसके ए मजबूत विधिक प्रणाली आवश्यकता है, जो महिला हितों रक्षा कर सके और उन्हें बराबरी हक और न्याय दिला सके। कह है कि समान नागरिक संहिता सबसे ज्यादा जरूरत मुस्तिम पुदय को है। ध्यान रहे जिस पुदय में कानूनी तौर पर हिलाओं को बराबरी का अधिकार न हो, वहाँ सामाजिक न्याय बात तो सोची भी नहीं जा सकती। अगर मुस्तिम समाज अपने रुद्धिवादी सोच को त्याग कर मुख्यधारा में जगह बनाना चाहता है और अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर करना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना होगा। समाज नागरिक संहिता इसकी एक बेहतरीन शुरूआत हो सकती है। हालांकि इसके लिए सरकारों को सबसे पहले समान नागरिक संहिता के प्रति मुस्तिम महिलाओं के कुछ भ्रमों को दूर करना चाहिए। समान नागरिक संहिता को लेकर मुस्तिम समाज के भीतर एक तरह का डर बैठा हुआ है। सरकार को इस पर खुलकर बात करने की जरूरत है। इसलिए और, क्योंकि अफवाहें फैलाई जा रही है। इसके चलते कुछ लोगों को लगता है कि समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद उनकी शादी करने का तरीका बदल जाएगा या फिर वे अपने अंतिम संस्कार के मौजूदा तरीके को नहीं निभा पाएंगे। इसी तरह कुछ लोगों को यह लगता है कि उन्हें अपनी वेश-भूषा बदलने को मजबूर किया जाएगा, जबकि समान नागरिक संहिता का इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। यह तो सिर्फ वह कानून है जिसके जरिये यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी के भी साथ कोई अन्याय न हो सके। मुस्तिम महिलाओं को यह खास तौर पर समझना होगा कि आल इंडिया मुस्तिम पर्सनल ला बोर्ड जैसे संगठन हमशा समान नागरिक संहिता का विरोध करेंगे और उसे गैर इस्तुमिक बताएंगे, क्योंकि उनके अस्तित्व का सवाल है। शायद इसीलिए आज तक मुस्तिम पर्सनल ला को संहिताबद्ध नहीं किया गया है। यह समझा जाना चाहिए कि जैसे माडल निकाहनामा में तत्काल तीन तलाक न देने के प्रविधिन शामिल किए गए हैं, उसी तरह की व्यवस्था समान नागरिक संहिता में भी की जा सकती है। इसी के साथ यह भी समझना होगा कि धर्म हमारा व्यक्तिगत मामला होना चाहिए, न कि सियासी।

दुनिया को राह दिखाता नया भारत, विश्व का नेतृत्व करने वाला एक सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत आकार लेगा

प्रधानमंत्री नरन्द्र मादा के नवृत्त में राजग सरकार ने केंद्र में अपने आठ वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवधि को मैं नए भारत के निर्माण की यात्रा के रूप में देखता हूं। नए भारत का अर्थ एक सशक्त, सक्षम, समर्थ और आत्मनिर्भरता की भावना यकृत भारत है। यह भारताय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़े गए हैं। भारत आज छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 'ईंज आफ हूँग बिजनेस' में भारत 2015 में जहां 142वें स्थान पर था, वहीं अब 63वें स्थान पर बाकास हा सबस्पृशा एवं सर्वसमावेशी माडल को लेकर आगे बढ़े गए हैं। इसका उद्देश्य देश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाते हुए उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। उज्ज्वला, आयुष्मान भारत,

ठ वर्षा में स्वतंत्रता के बाद पहली बार गरीब और पिछड़े सरकार में निधारक (स्टेक्होहॉल्डर) बने और विवरण्यवस्था की मुख्यधारा से ज़्रुद़। दी जी के शासन में राष्ट्रीय रक्षा को भी अभूतपूर्व मजबूती दी गई है। आतंकवाद के प्रति यह

पास गाठा-बारूद का कमा हा गइ है, लेकिन अब सेन्य बलों को सभी अत्याधुनिक संसाधनों एवं उपकरणों से लैस रखने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। आज देश की वायु सीमा की रक्षा राफेल जैसा अत्याधुनिक लड़ाकू विमान कर रहा है तो एस-400 जैसी जा का संयुक्त राष्ट्र साहत विश्व के कई मंच और देश सम्मानित कर चुके हैं। यह भी विश्व में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का ही दर्योतक है। पिछले आठ वर्षों में भारत की महान संस्कृति और परंपराओं को पुनर्स्थापित किया गया है। पश्चिमांतरी के पर्यावरण से भारतीय

A close-up photograph of a vibrant red Anthurium flower with a yellow center, surrounded by green leaves and other colorful flowers like purple violets in the background.

केवल यासीन को सजा मिलना पर्याप्त नहीं, कश्मीर के हालात बदलने के लिए अभी बहुत कुछ करना होगा

आखिरकार एनआइए की एक अदालत ने यासीन मलिक को आतंकी फॉर्डिंग समेत अन्य मामलों में दोषी पाते हुए उप्रकैद की सजा सुना दी। चूंकि यह फैसला विलंब से आया, इसलिए उस पर एक सीमा तक ही संतोष किया जा सकता है। ऐसे फैसले यही बताते हैं कि न्याय में देरी अन्याय है। यासीन मलिक न केवल खुद आतंकी गतिविधियों में शामिल था, बल्कि अन्य आतंकियों की हर तरह से मदद भी करता था। उसने वायु सेना के चार अफसरों की हत्या की और गीपी सिंह सरकार के समय गृहमंत्री रहे मुफ्ती मुहम्मद सईद की बेटी और महबूबा मुफ्ती की बहन रुबिया सईद का अपहरण किया। माना जाता है कि यह अपहरण नहीं था, बल्कि आतंकियों को छुड़ाने की एक साजिश थी और उसमें जम्मू-कश्मीर सरकार के भी कुछ लोग शामिल थे। जब रुबिया सईद की रिहाई के बदले खुंखार आतंकियों को छोड़ा गया तो आतंकियों का दुस्साहस चरम पर पहुंच गया और कश्मीरी हिंदुओं को मारने, धमकाने की घटनाएं तेज हो गईं। जब यासीन मलिक के साथियों ने जेकेएलएफ सरगना मकबूल बट्ट को फांसी की सजा सुनाने वाले जज नीलकंठ गंजू की हत्या कर दी तो कश्मीरी हिंदुओं के लिए वहां रहना मुश्किल हो गया

होना शुरू हो गया। अभी यासीन मलिक के अन्य मामलों की भी सुनवाई होनी है। देखना है कि उसे इन मामलों में क्या सजा मिलती है? उसने जिस तरह के आतंकी कृत्य किए हैं, उन्हें देखते हुए तो उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जो भी हो, यह समझना कठिन है कि 1994 में उसे जेल से क्यों छोड़ा गया? जेल से छूटते ही वह खुद को गांधीवादी कहने लगा। हारानी और पाकिस्तानरस्ते नेताओं के साथ तकालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी मिला और उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी से भी। वाजपेयी सरकार के समय उसे पासपोर्ट भी मुहैया करा दिया गया। इसके बाद वह अमेरिका, ब्रिटेन और पाकिस्तान की यात्रा करने लगा। पाकिस्तान जाकर उसने आतंकी सरगना हाफिज सईद के साथ मंच भी साझा किया। किसी



की बात यह रही कि कई बुद्धिजीवी, नेता और पत्रकार उसे सचमुच गांधीवादी बताने लगे और उसके हर तरह से सहायता भी करने लगे। नतीजा यह हुआ कि उसे विभिन्न कार्यक्रमों में बुलाया जाने लगा। वह सरकार के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात करने लगा। वह

किंतु का मसीहा बताने में लगे हुए ऐसा करने वालों ने केवल एक तंत्रिका का महिमांडन ही नहीं किया, बल्कि कश्मीर समस्या को टेल भी बनाया और उन तत्वों प्रोत्साहन दिया, जो कश्मीर आजादी का राग अलाप रहे यह अच्छा हुआ कि एनआईएर गतल ने यह पाया कि हुरियत फैस और तहरीक ए हुरियत ने संगठनों को आतंकी गिरोह नने के पर्याप्त प्रमाण हैं। क्या शर्मनाक नहीं कि ऐसे संगठनों खुद हमारी सरकारों ने वैधता न की और यह माहौल बनाया वे कश्मीर समस्या के समाधान सहायक बन सकते हैं? कश्मीर समस्या उसी समय शुरू हो थी, जब आजादी के बाद केस्तानी सेना ने कबालियों के में घाटी में हमला बोला। इस लेले में पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर कुछ हिस्सा हथिया लिया, गोंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री गहरलाल नेहरू ने सेना की ग़ह के विपरीत युद्धविराम करा या और मामले को संयुक्त राष्ट्र गए। वहां यह मामला उलझ गया। इसके बाद नेहरू ने जम्मू-कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 लाकर उसे कुछ विशेष अधिकार देए। यही विशेषाधिकार अलगाव र फिर आतंक का कारण बने। ही विशेषाधिकारों के कारण करने का भौमिका मिला और उसने वहां आतंकी जट्ठे भेजने शुरू कर दिए। यह सिलसिला अभी भी कायम है। कश्मीर के हालात बदलने तब शुरू हुए, जब 2014 में नरेन्द्र मोदी ने केंद्र की सत्ता संभाली। पाकिस्तान ने जब-जब कश्मीर में कोई नापाक हरकत की, तब-तब भारत ने उसे सबक सिखाया-पहले सर्जिकल स्ट्राइक के जरिये और फिर एयर स्ट्राइक के जरिये। अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35 ए को हटाने का साहसिक फैसला लिया। मोदी सरकार के कारण ही यासीन मलिक की गिरफतारी हुई और उसे सजा मिली, लेकिन अभी उसके जैसे न जाने कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी बाकी है। आखिर क्या कारण है कि शब्दीर शाह, मसरूर आलम, इंजीनियर रशीद, जहर अहमद शाह वटाली जैसे पाकिस्तान के एजेंटों अथवा बिट्टा कराटे सरीखे आतंकियों के खिलाफ चल रहे मामले तेजी नहीं पकड़ रहे हैं और वह भी तब जब उन पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़े? और आतंकियों की मदद करने के गंभीर आरोप हैं? इस सवाल के लिए जांच एजेंसियां भी जिम्मेदार हैं और न्यायपालिका की सुरक्षा भी। यह तय है कि यासीन मलिक को जो सजा सुनाई गई, उसे उच्चतर अदालतों में चुनौती दी जाएगी।

सकती। अगर मुस्लिम समाज अपने रुढ़िवादी सौच को त्याग कर मुख्यधारा में जगह बनाना चाहता है और अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर करना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना होगा। समाज नागरिक संहिता इसकी एक बेहतरीन शुरूआत हो सकती है। हालांकि इसके लिए सरकारों को सबसे पहले समाज नागरिक संहिता के प्रति मुस्लिम महिलाओं के कुछ भ्रमों को दूर करना चाहिए। समाज नागरिक संहिता को लेकर मुस्लिम समाज के भीतर एक तरह का डर बैठा हुआ है। सरकार को इस पर खुलकर बात करने की जरूरत है। इसलिए और, क्योंकि अफवाहें फैली जा रही है। इसके चलते कुछ लोगों को लगता है कि समाज नागरिक संहिता लागू होने के बाद उनकी शादी करने का तरीका बदल जाएगा या किर वे अपने अंतिम संस्कार के मौजूदा तरीके को नहीं निभा पाएंगे। इसी तरह कुछ लोगों को यह लगता है कि उन्हें अपनी वेश-भूषा बदलने को मजबूर किया जाएगा, जबकि समाज नागरिक संहिता का इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। यह तो सिर्फ वह कानून है जिसके जरिये यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी के भी साथ कोई अन्याय न हो सके। मुस्लिम महिलाओं को यह खास तौर पर समझना होगा कि आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड जैसे संगठन हमशा समाज नागरिक संहिता का विरोध करेंगे और उसे गैर इस्लामिक बताएंगे, क्योंकि उनके अस्तित्व का सवाल है। शायद इसीलिए आज तक मुस्लिम पर्सनल ला को संहिताबद्ध नहीं किया गया है। यह समझा जाना चाहिए कि जैसे मादल निकाहनामा में तत्काल तीन तलाक न देने के प्रविधान शामिल किए गए हैं, उसी तरह की व्यवस्था समाज नागरिक संहिता में भी की जा सकती है। इसी के साथ यह भी समझना होगा कि धर्म हमारा व्यक्तिगत मामला होना चाहिए, न कि सियासी।

बोर्ड पास छात्र-छात्राएं चिंता छोड़े बनाएं अपना भविष्य



एसके गुप्ता प्रधानाचार्य राजकीय आईटीआई नैनी, नैनी आईटीसी के अनुदेशकों से बात करते हुए।



आरके दुबे प्रधानाचार्य राजकीय आईटीआई भद्रोही नैनी आईटीसी की वेबसाइट का विमोचन करते हुए।

कार्यालय प्रधानाचार्य नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त)

सीधे प्रवेश सुचना

नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र में प्रस्तावित व्यक्तियोगी में अगस्त 2021 में प्रारम्भ होने वाले शास्त्र में प्रवेश हेतु इंजीनियरिंग एवं नैनी इंजीनियरिंग प्रशिक्षण कोर्स क्लास, फिटर, ऐसिक कल्याणिंग, आटा एन्टी ऑपोलोल, कायर फ्रीमेनाल एवं इण्डस्ट्रीयल सोफ्टवर, नियोरिटी सार्किल, कल्पनाल हाईवेयर असेंबली एवं मैनेटेनेंस, सार्टिफिकेट हृषक न्यूट्रिट एप्लीकेशन (सीएनीएल), इलेक्ट्रिकल टेक्निकलिंग, रेफिलरेशन प्रूफ एयर कंप्रेसनिंग, योगा अशिस्टेंट, लैलिंग टेक्नोलॉजी, सीटिंगनल्स, प्रोजेक्शन एन्ड ऑपरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कल्पनाल टीचर ट्रेनिंग कोर्स के लिए न्युनतम शैक्षिक योग्यता लाईस्युल उल्लिखित है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया :— इस प्रक्रिया के लिए हमारी वेबसाइट www.nainiiti.com पर जाएँ Student's Zone → Online Form → Choose Course → Apply Now

यह आपने व्यवसाय कोर्स का चयन कर आपना प्रवेश सुनिश्चित करें।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया :— इस प्रक्रिया में प्रशिक्षणार्थी अपनी शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, आवार कार्ड एवं 4 पासपोर्ट चाहज कोटीयाक के साथ प्रवेश कार्यालय में शामिल करें।

नोट-: प्रवेश प्राप्त करने की अनितम तिथि 30 अक्टूबर 2021 है।

अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए

visit us at : www.nainiiti.com

प्रवेश कार्यालय :- त्रिलोकपुरी प्लाजा टीसरी मॉडिल,
एम.जी. मार्ग, चिकित्सा लाइन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

फोन करें :- 0532-2695850, 9415608710, 6394370734,
7355448437, 6386474074, 6306080178, 9026359274

बोर्ड पास छात्र-छात्राएं चिंता छोड़े बनाएं अपना भविष्य...

नैनी/इलाहाबाद। इलाहाबाद यूपी एवं सीबीएसई बोर्ड से हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षाओं में सफल छात्र-छात्राओं के पास अपना भविष्य बनाने का सुनहरा मोका है। ऐसे अभ्यर्थी को भविष्य बनाने का मोका नैनी इंडिस्ट्रियल इंस्टीट्यूट दे रहा है। यह जापि बिना अतिरिक्त समय गणना से तीनों बोर्ड के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इन बोर्ड परीक्षाओं में उत्तर्ण प्रदेश के तकरीबन छ्वीस लाख विद्यार्थियों के सामने उच्च शिक्षा के साथ अच्छे करियर की भी चिंता है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए इंडिस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईटीआई में चलने वाले कोर्सेज फॉर्म स्पष्ट के रूप में सामने आए हैं। थीरे-थीरे यह रोजगार की गारंटी बनते हैं। इसके अलावा आईटीआई में एक लाख से अधिक विद्यार्थी की मांग है। इसके विपरीत हर साल मात्र तीस हजार प्रशिक्षित युवा मिल रहे हैं। इसके अलावा इन दिनों हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट समेत कई विभागों में सैकड़ों पदों के लिए आईटीआई पास अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं। आईटीआई पास अभ्यर्थियों के लिए रेलवे में डेरों संभाननाएं हैं ऐसे में विशेषज्ञों की सलाह है कि पंखरागत कोर्स के साथ युवा आईटीआई की ओर ध्यान देकर बेहतर कैरियर प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर तथा

पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह एक बेहतर विकल्प है। औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के प्रवत्ता दरूण स्वरजा से हुई खास बातचीत में उहने इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी।

पृष्ठ- गण सवाल

उत्तर- नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र क्या है? इसके बारे में बताएं।

उत्तर- नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र जो नैनी परीक्षाएं एवं समय पर परीक्षा परिणाम का अपग्रेड़िशन। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम बेहतर लोसेमेंट सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियों का सूर गठित आयोजन विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास मूल्य एवं गुणवत्ता आधारित शिक्षा, व्यवस्थित एवं सुनियोजित एवेंडामेंट कैंड्र डर, डीविएटेड टू एजवेशन मिशन को पूरा करने वें उद्देश्य से संस्थान 9 वर्षों से प्रयासरत है। केंद्र से आज तक 5000 से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया जा चुका है एवं केंद्र द्वारा प्रशिक्षित छात्र छात्राएं इस समय सफलता प्राप्त कर चुके हैं। सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को भारत सरकार द्वारा प्रमाण पत्र दिए जाते हैं जो देश विदेश में सभी जगह मान्य है।



द्वारा मान्यता प्राप्त है। एनसीबीटी-डीजीटी-नई दिल्ली, एनआईओएस - नई दिल्ली।

प्रश्न- नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में अध्ययन से क्या लाभ है?

उत्तर- गर्तमान परिवृद्धि में पाठ्यक्रम आईटीआई द्वारा समय पर परीक्षाएं एवं समय पर परीक्षा परिणाम का अपग्रेड़िशन। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम बेहतर लोसेमेंट सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियों का सूर गठित आयोजन विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास मूल्य एवं गुणवत्ता आधारित शिक्षा, व्यवस्थित एवं सुनियोजित एवेंडामेंट कैंड्र डर, डीविएटेड टू एजवेशन मिशन को पूरा करने वें उद्देश्य से संस्थान 9 वर्षों से प्रयासरत है। केंद्र से आज तक 5000 से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया जा चुका है एवं केंद्र द्वारा प्रशिक्षित छात्र छात्राएं इस समय सफलता प्राप्त कर चुके हैं। सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को भारत सरकार द्वारा प्रमाण पत्र दिए जाते हैं जो देश विदेश में सभी जगह मान्य है।

प्रश्न- नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में कौन से पाठ्यक्रम संचालित हैं?

उत्तर- कोण (कम्प्यूटर अपरेटर एण्ड प्रोग्रेमिंग आसिस्टेंट), फैटर, बेसिक कम्प्यूटिंग, डाटा एंट्री ऑपरेशन, फायर प्रीवेशन एंड इंडिस्ट्रियल सेफ्टी, सिक्युरिटी सर्विस, कम्प्यूटर हार्डवेयर एंड मैटेनेंस इन कंप्यूटर एंड ऑफीसेन्स, इलेक्ट्रिकल ट्रैकिंग इन एयर कंट्रोल्यार्म, योग असिस्टेंट, वैल्डग ट्रैकोलॉजी, सीएनसी प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेशन, इलेक्ट्रिक्सियन, कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग, इत्यादि।

प्रश्न- आपके औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र एवं अन्य प्रशिक्षण केंद्रों में क्या अंतर है?

उत्तर- नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र अंतर्राष्ट्रीय मानक आई.एस.ओ प्रमाणित है एवं श्रम रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसकी स्टार (सिस्टर) प्रैंडिंग की गई है एवं एम.आई.एस.डिफेंस मिनिस्ट्री भारत सरकार द्वारा अधिकृत प्रशिक्षण केंद्र भी नियुक्त किया गया है। अत्यधिक जानकारी के लिए आप फोन भी कर सकते हैं हमारे फोन नंबर इस प्रकार है- 0532-26958959, 9415608710, 9415608783, 9415608790, 7380468640, 6394370734।



सृष्टि सिंह मिसेज एशिया पेसिफिक नैनी आईटीसी के छात्रों को साथ।